

बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार तिथि २६ अप्रील १९६० को ११ बजे अपराह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

अनागत तारांकित प्रश्नों का उत्तर मेज पर रखा जाना ।

श्री जगत नारायण लाल—महोदय, मैं गत षष्ठ सत्र, सितम्बर—दिसम्बर, १९५९ के

शेष ७५५ अनागत प्रश्नों में से ७१ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर मेज पर रखता हूँ । शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे ।

सूची ।

क्रम सं० ।	सदस्य का नाम ।	प्रश्न संख्या ।
१	श्री प्रभु नारायण राय	१७, १९७, ३५८, ३५९ ।
२	श्री बैद्यनाथ प्रसाद सिंह	७१, ३४८, १०४९ ।
३	श्री शिव महादेव प्रसाद	७३ ।
४	श्री हरिवंश नारायण सिंह	७६ ।
५	श्री श्याम चरण मुर्मू	११४ ।
६	श्री तारा प्रसाद बक्शी	१५५, १५६ ।
७	श्री महावीर राउत	१७२, १२२३ ।
८	श्री रामानन्द तिवारी	१७३, ७३९ ।
९	श्री व्रजनन्दन शर्मा	१८६, ७३०, १२०६ ।
१०	श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल	२३५ ।
११	श्री अब्दुल गफ्फूर	२४८ ।
१२	श्री इगनेश कुजूर	३४३ ।
१३	श्री जय नारायण झा 'विनीत'	३६२, ६७७, ८२४, १३६६ ।
१४	श्री एस० के० बागें	३६४, ८१२, १२४६ ।
१५	श्री राजाराम शर्मा	३६५ ।
१६	श्री कैलाशपति सिंह	३६६ ।
१७	श्री सभापति सिंह	३६७ ।
१८	श्री जी० पी० त्रिपाठी	३६९ ।

श्री मकबूल अहमद—(१) और (२) उत्तर स्वीकारात्मक है। चूंकि देवुषा

यूनियन बोर्ड विघटित हो चुका है अब यह पावना जिला, परिषद्, दरभंगा को चुकाना है। विशेष पदाधिकारी, जिला परिषद्, दरभंगा ने यूनियन बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष से श्री हरिदेव पाठक, लिपिक की महंगाई भत्ता का बिल वो उनका पूरा पता मांगा था जो अभी तक प्राप्त नहीं है। जिला परिषद् को आदेश दिया जा रहा है कि इस पावना को चुकती शीघ्रातिशीघ्र कर दें।

पुल का निर्माण।

१३७८। श्री लखण लाल कपूर—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा

करें कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौड़ी थाना के मसौड़ी-एकनर-सराय रोड में दरवा नदी के निकट पुल टूट जाने के कारण आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है; यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल को तुरन्त बनवाने का विचार रखती है?

श्री मकबूल अहमद—पहले भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तथा दूसरे भाग के

बारे में यह कहना है कि वर्षा काल के बाद पुल की गंथासंभव मरम्मत कर सड़क बहाल कर दी गई है। पुल को पूरी तरह मरम्मत करने के लिए स्टीमेट स्कीम चलायी गयी है। आशा की जाती है कि मरम्मत का काम शीघ्र ही आरंभ किया जायगा।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

NON-PAYMENT OF DEARNESS ALLOWANCE.

236. Shri RAMJANAM MAHTO : Will the Education Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that dearness allowance, annual increment in pay and other facilities permissible under the rules to teachers of the Dhanoura Madhyamic Vidya Mandir in Colgong P.S. of Bhagalpur district have not been given to them by the District Education Office, Bhagalpur since August, 1959;

(2) if the answer to the above clause be in the affirmative, what steps Government propose to take in this matter?

*श्री कृष्णकान्त सिंह—(१) उत्तर नकारात्मक है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

*श्री रामजनम महतो—क्या सरकार का कहने का मतलब है कि अबतक पेमेंट नहीं गया है?

श्री कृष्णकान्त सिंह—जी, हां।

PAYMENT OF ARREAR TO SHRI BHOLA MAHTON.

237. **Shri SHITAL PRASAD BHAGAT** : Will the Education Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that one Shree Bhola Mahton, a retired Head teacher of Board U.P. School, Langoon, P.S. Amarpur, district Bhagalpur, has not yet been paid his provident fund money;

(2) whether it is a fact that he has not also been paid his salary for January, 1954;

(3) if the answers to the above clauses be in the affirmative, do Government propose to pay at an early date his provident fund amount as well as the salary for January, 1954, if not, why?

श्री कृष्णकान्त सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) बांका लोकल बोर्ड के अधीन काम करने वाले शिक्षकों का प्रोविडेंट फंड का हिसाब १९४९ से १९५४ तक का अभी तक नहीं हो सका है। विशेष पदाधिकारी जिला बोर्ड के आदेशानुसार इस अवधि का हिसाब-किताब ठीक किया जा रहा है। निकट भविष्य में ही यह काम पूरा हो जायगा। जिला परिषद् से शिक्षकों के द्वारा जमा किया हुआ रुपया निधि का भुगतान कर दिया जायगा।

जनवरी, १९५४ का वेतन देने के लिये प्रधानाध्यापक से "बिल" की मांग की जा चुकी है। प्राप्त होते ही उनके बकाये वेतन का भुगतान भी कर दिया जायगा।

*श्री शीतल प्रसाद भगत—मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि ६-६ वर्ष हो गये

अभी तक शिक्षकों का प्रोविडेंट फंड नहीं मिला जबकि पहले साल-साल भर में मिल जाता था तो इसके बारे में सरकार क्या नीति है?

श्री कृष्णकान्त सिंह—नीति तो आपको मालूम है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जब स्पेशल अफसर के अधीन आया तो उसका सारा हिसाब-किताब हो रहा है। ४९ से ५४ तक के हिसाब-